RAJHIN/2014/55262

sancharjagat.com

खबरों व विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
संचार जगत
मो.नम्बर:- +917357161599

संचार जगत

दैनिक समाचार पत्र

sancharjagat.com

editorial@sancharjagat.com

'सोच को इतना बड़ा रखो कि असफलता भी एक छोटा कदम लगे। सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक दिशा है। बड़ा सोचो, बड़ा करो।'

वर्ष:13 | अंक: 287 | जयपुर, शुक्रवार, 20 नवम्बर 2026 | मूल्य: 2.00 रूपए | पृष्ठ : 4

कंपनियों से मोदी बोले- आपकी भूख इतनी है कि पेट नहीं भरता

FICCI के कार्यक्रम में कहा- मैंने टैक्स छूट दी, आपने क्या किया, न सैलरी बढ़ाई, न नौकरियां

नई दिल्ली/संचार जगत



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के बड़े कॉर्पोरेट्स पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कंपनियों को टैक्स में राहत दी, लेकिन उन्होंने इसका फायदा अपने तक ही रखा। न तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई और न ही नई नौकरियां पैदा करने के लिए जरूरी कदम उठाए।

पीएम मोदी ने कारोबारियों से पूछा कि क्या इसी तरह काम चलता रहेगा? पीएम मोदी ने यह बात दिल्ली के भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) के कार्यक्रम में कही। संगठन के 100 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई बड़े कारोबारी मौजूद थे। कॉर्पोरेट्स के सामने पीएम की यह पहली ऐसी सख्त टिप्पणी थी।

कंपनियों से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं आम लोग

भारत में अब व्यक्तिगत आयकर से सरकार को कॉरपोरेट टैक्स के मुकाबले ज्यादा कमाई हो रही है। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) से सरकार को 10.45 लाख करोड़ रुपये मिले। वहीं, कंपनियों से कॉरपोरेट टैक्स के रूप में 9.11 लाख करोड़ रुपये आए। यह पहली बार वित्त वर्ष 2020-21 में हुआ था, जब व्यक्तिगत आयकर से 4.88 लाख करोड़ रुपये मिले थे, जबकि कॉरपोरेट टैक्स से 4.58 लाख करोड़ रुपये आए। वित्त वर्ष 2021-22 में कॉरपोरेट टैक्स फिर आगे निकल गया। इसके बाद 2022-23 में व्यक्तिगत आयकर ने दोबारा बढ़त बना ली।

132 साल पुराने जेल कानून की जगह नया नियम

नई दिल्ली, आरएनएन। कभी अंग्रेजों के दौर में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखने के लिए बदनाम रहा अंडमान का काला पानी (आधिकारिक रूप से सेलुलर जेल) अब जेल व्यवस्था में बदलाव की नई कहानी लिखने जा रहा है। यहां जेलों को सिर्फ सजा देने की जगह कैदियों को सुधारने, उन्हें हुनर सिखाने और समाज में दोबारा सम्मान के साथ जीवन शुरू करने के लिए तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।

जेल बनेगी सुधार गृह, शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास पर जोर

इसके लिए 132 साल पुराने अंग्रेजों के जेल कानून को बदलने की पहल की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए नया जेल नियम, 2026 लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति ने 17 नवंबर को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत इस नियम को जारी किया।

EPFO का फैसला, हर महीने निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा

खाते में न्यूनतम बैलेंस सीमा 10% हुई, नौकरी जाने पर दो महीने में निकाल सकेंगे पीएफ का पूरा पैसा

नई दिल्ली/संचार जगत



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने करोड़ों पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी है।

संगठन ने रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा एक साथ निकालने के बजाय हर महीने, तीन महीने या सालाना किस्तों में निकालने की सुविधा को मंजूरी दे दी है। इसे सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) कहा जाता है। इसके अलावा पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, नौकरी छूटने के बाद पूरा पीएफ निकालने के लिए इंतजार की अवधि भी 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की गुरुवार 19 नवंबर को हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की।

किस मकसद के लिए पैसा निकाल सकते हैं...

नई योजना के तहत कर्मचारी और उनके परिवार की कई प्रमुख जरूरतों के लिए आंशिक निकासी की अनुमति दी गई है। खुद की या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी और अस्पताल का बिल भरने के लिए। बच्चों और परिवार के सदस्यों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च उठाने के लिए। शादी के खर्चों के लिए। नया घर या फ्लैट खरीदने, जमीन खरीदने, मकान बनवाने, होम लोन चुकाने या पुराने घर की मरम्मत कराने के लिए। किसी अचानक आई बड़ी मुसीबत में भी पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। क्या पीएफ का पैसा निकालने पर टैक्स लगता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी ने कितने साल तक नौकरी की है। कुछ मामलों में 10 प्रतिशत टीडीएस लग सकता है।

भारत अब एक समृद्ध देश लेकिन स्वच्छता में खराब

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खराब साफ-सफाई समाज व देश की छवि को धूमिल करती हैं

नई दिल्ली/संचार जगत

उच्चतम न्यायालय ने ठोस कूड़ा प्रबंधन नियमों को लागू न किए जाने पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत अब एक समृद्ध देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में इसका प्रदर्शन खराब है।

ठोस कूड़ा प्रबंधन नियमों के तहत नगर निगमों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के पालन से जुड़े राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने माना कि ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम, 2025 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने और प्रक्रिया शुरू करने जैसे शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं।पीठ ने 17 नवंबर के अपने आदेश में कहा, अदालत ने गौर किया कि भारत अब एक समृद्ध देश है।

कोर्ट ने क्या कहा

- संविधान में शक्तियों का बंटवारा उसकी मूल संरचना का हिस्सा है। संसद ने एन्वायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 बनाया है। कार्यपालिका ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 बनाए हैं।
- कानून और नियम मौजूद होने के बावजूद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स तय लक्ष्य से कम है।
- सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार का संरक्षक है। इसलिए हमने एससीएमसी के जरिए स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश देने की जिम्मेदारी उठाई है।
- एससीएमसी के जरिए सुप्रीम कोर्ट की यह कोशिश पांचवें पहिए की तरह नहीं है, जो बाकी चार पहियों को चलाने की कोशिश कर रहा हो।

एक्टर सैफ अली खान को जान से मारने की धमकी

मुम्बई, आरएनएन। बॉलीवुड सितारों को धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। अब अभिनेता सैफ अली खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, अभिनेता सैफ अली खान के फोन पर जीशान अख्तर के नाम से एक वॉयस मैसेज आया, जिसमें कहा गया कि उनका भी वही हश्र होगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये धमकी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांछित आरोपी जीशान अख्तर ने दी है। बहरहाल, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि जीशान ने ही खान को धमकी दी है। तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं।



असमानता मप्र में 1,651, बिहार में 1,126 और यूपी में प्रति व्यक्ति खर्च हुए 1,399 रुपये, सिक्किम में सबसे ज्यादा

देश में प्रति व्यक्ति औसत सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2,959 रु.

नई दिल्ली/संचार जगत

देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च के मामले में राज्यों के बीच भारी क्षेत्रीय असमानता सामने आई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे आर्थिक रूप से कमजोर और अधिक आबादी इन राज्यों की सरकारें प्रति व्यक्ति के स्वास्थ्य पर औसतन महज 1,651 रुपये कर खर्च कर रही हैं। यह आंकड़े पूर्वोत्तर राज्यों के औसत 3,501 रुपये के आधे से भी कम हैं। जबकि केंद्रशासित प्रदेशों के औसत 7,209 रुपये का करीब एक चौथाई है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के 2023-24 के आंकड़ों से यह तस्वीर सामने आई है। एनएचए के अनुमानों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में देश में सरकारों का कुल स्वास्थ्य खर्च 4.1 लाख करोड़ रुपये रहा। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2,959 रुपये रहा। कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकारी हिस्सेदारी 43.5 प्रतिशत थी, जबकि यह देश की जीडीपी का 1.43 प्रतिशत रहा।



कमजोर राज्यों के सामने संसाधनों की चुनौती

स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉ. चंद्रकांत लहरिया के मुताबिक, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च में अंतर राज्यों की वित्तीय क्षमता, आबादी के आकार, स्वास्थ्य ढांचे में पहले हुए निवेश और राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर और अधिक आबादी वाले राज्यों के सामने संसाधनों की कमी की चुनौती रहती है। दूसरी ओर, पूर्वोत्तर राज्यों में दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और बिखरी हुई आबादी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की लागत अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में कम आबादी के बावजूद बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रति व्यक्ति अधिक निवेश करना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण जैसे कई खर्च ऐसे होते हैं, जो मरीजों की संख्या कम होने पर भी लगभग उतने ही बने रहते हैं।

केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे आगे

केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च का औसत 7,209 रुपये प्रति व्यक्ति रहा। चंडीगढ़ इस मामले में सबसे आगे रहा, जहां प्रति व्यक्ति 24,187 रुपये खर्च किए गए। पुडुचेरी में यह आंकड़ा 11,165 रुपये, लक्षद्वीप में 9,643 रुपये, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 8,947 रुपये और दिल्ली में 8,611 रुपये रहा। जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 3,339 रुपये दर्ज किया गया। वहीं, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में यह 2,293 रुपये रहा। पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों में भी सरकारी स्वास्थ्य खर्च के आंकड़ों में काफी अंतर है। असम में प्रति व्यक्ति 2,282 रुपये और त्रिपुरा में 3,360 रुपये खर्च किए गए। वहीं, सिक्किम में यह रकम 16,026 रुपये, मिजोरम में 9,320 रुपये, अरुणाचल प्रदेश में 8,885 रुपये और मेघालय में 7,533 रुपये रही। मणिपुर में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 5,507 रुपये और नगालैंड में 4,585 रुपये दर्ज किया गया। इन आठ राज्यों का जनसंख्या के आधार पर औसत 3,501 रुपये रहा।

पीयूसी के बदले नियम

बीएस-6 गाड़ी को तीन साल की दी गई राहत

नई दिल्ली/संचार जगत



सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसका प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी पीयूसी भी बेहद अहम दस्तावेज है।

अक्सर वाहन मालिकों को तय समय पर इसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता को लेकर नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के बाद हर वाहन के लिए पीयूसी की अवधि एक जैसी नहीं रहेगी। यह इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, उसका एमिशन स्टैंडर्ड क्या है और वह निजी इस्तेमाल में है या ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में आती है। ऐसे में अगर आपके पास बीएस-4 या पुरानी गाड़ी है तो यह बदलाव आपके लिए जानना जरूरी है।

पुरानी गाड़ियों का सर्टिफिकेट 6 महीने में होगा रिन्यू

सेना प्रमुख ने चेक गणराज्य के सशस्त्र बलों के मुख्यालय का किया दौरा

संचार जगत



नई दिल्ली। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने चेक गणराज्य के सशस्त्र बलों के मुख्यालय का दौरा किया है। इस यात्रा के दौरान जनरल धीरज सेठ ने चेक सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रथम उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पेट्र चेपेल्का से मुलाकात की।

दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात पर वार्ता हुई। यहां भारत और चेक गणराज्य के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने तथा दोनों देशों की सेनाओं के बीच पेशेवर सैन्य आदान-प्रदान को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। जनरल धीरज सेठ को चेक सशस्त्र बलों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने होराइजन 2035: थल युद्ध का आधुनिकीकरण और भविष्य की तैयारियां विषय पर विस्तृत जानकारी दी।

इसमें भविष्य के युद्धों की बदलती प्रकृति, नई तकनीकों के इस्तेमाल, सैन्य क्षमताओं में बदलाव और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना की तैयारियों से जुड़े अहम पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। चेक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर गए जनरल धीरज सेठ ने प्राग स्थित चेक सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ मुख्यालय में पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद सैनिकों को नमन किया।

वैन गॉग की पेंटिंग ने नया रिकॉर्ड बनाया



वाशिंगटन, आरएनएन। विंसेंट वैन गॉग की एक पेंटिंग ने इस डच चित्रकार की नीलामी के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यह कृति 19.04 करोड़ अमेरिकी डॉलर की भारी-भरकम कीमत पर नीलाम हुई है। नीलामी घर सोदबी ने कहा कि ''चेस्टनट ट्रीज़ इन ब्लॉसम'' नामक पेंटिंग के विक्रेता और इसके पिछले यहूदी मालिकों के बीच एक समझौते के बाद बुधवार को न्यूयॉर्क में इस रचना की बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ी। साल 1890 में प्रसिद्ध कलाकार की मृत्यु से पहले की अंतिम कृतियों में से एक, यह पेंटिंग नाजी जर्मनी के दौर की लूट का हिस्सा होने के विवाद में घिरी हुई थी। इस कलाकृति के मालिक ब्लाक्वियर-एरीटा परिवार ने कहा कि फिशर के उत्तराधिकारियों के साथ एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचकर हमें खुशी हो रही है।

कला के कद्रदानों ने सफाई का किया आह्वान

संचार जगत



नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुनक नहर पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से राजधानी को साफ और हरा-भरा रखने की अपील की। इस अभियान में अभिनेत्री ईशा गुप्ता, अभिनेता जैकी श्रॉफ और सिंगर बिस्मिल और स्टेबिन बेन भी शामिल हुए। सभी ने लोगों से शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देने की अपील की। सफाई अभियान के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल सिर्फ मुनक नहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद पूरी दिल्ली में सफाई को लेकर जागरूकता फैलाना है। इसमें यमुना नदी को साफ रखना भी शामिल है। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने भी लोगों से पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और इधर-उधर कचरा न फेंकने की अपील की। वहीं, अभिनेता जैकी श्रॉफ ने इस पहल की तारीफ करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से ऐसे अभियानों में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि लोगों को खुद आगे आकर काम करना होगा।

यूपी में कोहरे से भिड़े कई वाहन, पांच लोगों की मौत, 36 घायल

संचार जगत



कानपुर। उत्तर प्रदेश में दो अलग-अलग सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 अन्य घायल हो गए। कानपुर देहात में श्रद्धालुओं से भरी बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। वहीं, आजमगढ़ में घने कोहरे के कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कई वाहनों की टक्कर में तीन लोगों की जान चली गई और 14 लोग घायल हो गए। पहला हादसा कानपुर देहात जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ख्वाजा फूल इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर हुआ। यहां श्रद्धालुओं से भरी बस आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। बस में कुल 33 लोग सवार थे। ये सभी उन्नाव जिले के रहने वाले थे और राजस्थान में तीर्थयात्रा के लिए गए थे। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के बाद वे वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं, दूसरा बड़ा हादसा आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ। यहां घने कोहरे के बीच कई वाहन आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। बताया गया कि घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से यह दुर्घटना हुई।

पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती आज

संचार जगत



जयपुर। पंचायत चुनावों को लेकर बना राजनीतिक सस्पेंस आज खत्म हो रहा है। 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति वार्डों के लिए वोटों की गिनती और इन नतीजों से ग्रामीण राजस्थान में राजनीतिक संतुलन तय होगा और जिला प्रमुखों और प्रधानों के चुनाव का रास्ता साफ होगा। मतगणना सुबह 8 बजे सभी 37 जिलों के मुख्यालयों में शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव 41 जिलों के 1,403 जिला परिषद वार्डों और 457 पंचायत समितियों के 8,245 पंचायत समिति वार्डों के लिए कराए गए थे। हालांकि आज होने वाली मतगणना में 37 जिलों के 1,275 जिला परिषद वार्ड और 7,543 पंचायत समिति वार्ड शामिल होंगे। कोटा, बारां, करौली और श्री गंगानगर में, 128 जिला परिषद वार्डों और 702 पंचायत समिति वार्डों के लिए मतगणना 17 दिसंबर को अलग से होगी।

संपादकीय

कोयले की खपत घटा सकती है पराली

वायु प्रदूषण को लेकर तमाम चर्चा और चिंता के बाद भी विभिन्न हिस्सों से पराली यानी फसलों के अवशेष जलाए जाने के समाचार आने बंद नहीं हो रहे हैं। यद्यपि पराली दहन वायु प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं, लेकिन वह उसे बढ़ाने का काम करता है। अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी फसलों के अवशेष जलाए जाने लगे हैं। हर साल बड़ी मात्रा में पराली का काफी हिस्सा उचित प्रबंधन के अभाव में खेतों में जला दिया जाता है। ऐसा करने से रोकने के उपायों के साथ ही क्या फसल अवशेषों का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में करके कोयले पर निर्भरता कुछ कम की जा सकती है? तकनीकी आकलन इस दिशा में संभावनाएं जगाते हैं। फसल के अवशेषों को सीधे बिजली संयंत्रों में इस्तेमाल करना आसान नहीं। उनकी नमी, कम घनत्व, आकार और अन्य कारणों से उसे कोयले की तरह संभालना और उपयोग करना चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए पहले उसे छोटे आकार के ठोस ईंधन यानी बायोमास पेलेट में बदला जाता है। पेलेट तैयार होने के बाद उसे कोयले के साथ मिलाकर ताप विद्युत संयंत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को सह-दहन कहा जाता है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बिजली उत्पादन के लिए पहले से मौजूद संयंत्रों और आधारभूत ढांचे का उपयोग किया जा सकता है। यानी हर स्थिति में नया बिजली संयंत्र बनाने की जरूरत नहीं। तकनीकी आकलन के अनुसार कुछ ताप विद्युत संयंत्रों में पारंपरिक पेलेट का लगभग 10 प्रतिशत तक वजन आधारित मिश्रण बड़े बदलाव के बिना व्यावहारिक हो सकता है। हालांकि वास्तविक अनुपात संयंत्र की तकनीक, कोयले की गुणवत्ता और संचालन संबंधी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक है टोरिफिकेशन। इसमें कृषि अवशेष को लगभग 200 से 300 डिग्री तापमान पर नियंत्रित परिस्थितियों में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया से जैव ईंधन के कुछ गुणों में सुधार होता है। इसकी ऊष्मीय क्षमता बढ़ती है और नमी के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ता है। एक परीक्षण में सामान्य नमूने का ऊष्मीय मान लगभग 2,951 किलो कैलोरी प्रति किलो था, जो 230 डिग्री तापमान पर उपचार के बाद बढ़कर करीब 3,593 किलो कैलोरी प्रति किलो और 260 डिग्री पर लगभग 3,897 किलो कैलोरी प्रति किलो तक पहुंचा। अलग-अलग प्रकार की पराली और प्रसंस्करण परिणाम बदल सकते हैं। इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण उत्तर प्रदेश के टांडा में 110 मेगावाट क्षमता वाला संयंत्र है। स्पष्ट है कि कृषि अवशेषों को बेहतर तरीके से प्रसंस्कृत करके बिजली उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की संभावनाएं हैं। हालांकि हर संयंत्र की मशीनरी, ईंधन व्यवस्था और उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का अलग से आकलन जरूरी है। इस बदलाव का लाभ केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। चूंकि बिजली संयंत्रों को नियमित रूप से कृषि अवशेष से बने पेलेट की जरूरत होगी, अतः किसानों के लिए पराली का एक नया बाजार तैयार हो सकता है। गांवों में पराली संग्रह, गांठ बनाने, सुखाने, पेलेट निर्माण और परिवहन से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। किसानों को भी पराली के निस्तारण के लिए खर्च करने के बजाय उससे आमदनी मिलने की संभावना बनेगी, इस व्यवस्था की सफलता के लिए सबसे जरूरी है कच्चे माल की नियमित आपूर्ति।

भवनों के ढांचे में नवाचार

इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आइजीबीसी) के अनुसार, पारंपरिक इमारतों की तुलना में ग्रीन बिल्डिंग्स 20 से 30 प्रतिशत कम ऊर्जा की खपत करती हैं। सरकारी स्रोतों के अनुसार, भारत के वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी लाने और 2070 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी (कार्बन तटस्थता) हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करने में ग्रीन बिल्डिंग्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आइजीबीसी), ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हैबिटैट असेसमेंट और वैश्विक स्तर पर एलईईडी (लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायर्नमेंटल डिजाइन) जैसे मानक और प्रमाणन एक ढांचा प्रदान करते हैं।



भारत में इमारतों की ऊंचाइयां जैसे-जैसे बढ़ती जा रही हैं, जमीन और आसमान- दोनों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज शहरी विकास की चर्चा मुख्य रूप से 'स्मार्ट' और 'हरित' (पर्यावरण-अनुकूल) निर्माण पर केंद्रित है। इस क्षेत्र में पिछले तीन दशकों के दौरान एक बड़ा बदलाव दिखा है, जहां सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) अब कोई गौण विषय नहीं, बल्कि आर्किटेक्चरल डिजाइन और बिल्डिंग मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा बन गई है। ऊर्जा की बढ़ती लागत, लंबे समय में किफायती होना, सस्टेनेबिलिटी से जुड़े वादे और पर्यावरण-अनुकूल व उच्च-क्षमता वाली इमारतों की मांग- ये कुछ ऐसे कारक हैं जो इस बदलाव को बढ़ावा दे रहे हैं।

इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आइजीबीसी) के अनुसार, पारंपरिक इमारतों की तुलना में ग्रीन बिल्डिंग्स 20 से 30 प्रतिशत कम ऊर्जा की खपत करती हैं। सरकारी स्रोतों के अनुसार, भारत के वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी लाने और 2070 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी (कार्बन तटस्थता) हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करने में ग्रीन बिल्डिंग्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आइजीबीसी), ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हैबिटैट असेसमेंट और वैश्विक स्तर पर एलईईडी (लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायर्नमेंटल डिजाइन) जैसे मानक और प्रमाणन एक ढांचा प्रदान करते हैं। ये ऊर्जा की खपत, पानी के इस्तेमाल, कचरा प्रबंधन और इनडोर पर्यावरण की गुणवत्ता जैसे पैमानों के आधार पर किसी इमारत का मूल्यांकन करते हैं। ग्रीन बिल्डिंग में लंबे समय से सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी दिखाई देने वाली चीजों पर ध्यान दिया जाता रहा है। लेकिन अब सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) पर काम करते समय, डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग के मुख्य सिस्टम में नए अवसर तलाश रहे हैं। यहीं पर लिफ्ट और एस्केलेटर एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। लिफ्ट और एस्केलेटर इमारतों में बहुत अधिक उपयोग होने वाले सिस्टम हैं, जो लोगों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। ये किसी इमारत के रोजमर्रा के कामकाज का एक अहम हिस्सा हैं, जो ऊर्जा की खपत, लोगों के आराम, पहुंच, सुरक्षा और कुल कार्यक्षमता पर असर डालते हैं। स्मार्ट लिफ्ट किसी इमारत के 'सेंट्रल नर्वस सिस्टम' (केंद्रीय तंत्रिका तंत्र) की तरह काम कर सकती हैं, ये डाटा और कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करके परफार्मेंस को बेहतर बनाती हैं और ऊर्जा की बचत में मदद करती हैं। इस तरह ये अधिक स्मार्ट, कुशल और टिकाऊ इमारतों के निर्माण में एक बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। यह कार्यक्षमता भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किए गए डिजाइन का परिणाम है। इसके अलावा, एलईडी लाइटिंग, उच्च-क्षमता वाली मोटरें और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (जहां लागू हो) बिजली की खपत को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सहायक हो सकते हैं। समय से आगे सोचने की जरूरत : इंटेलिजेंट तकनीकें केवल ऊर्जा से जुड़ी सुविधाओं तक ही सीमित नहीं हैं। 'डेस्टिनेशन डिस्पैच सिस्टम' की मदद से लिफ्ट आस-पास की मंजिलों पर जाने वाले यात्रियों को एक साथ समूहित (ग्रुप) कर सकती हैं। इससे अनावश्यक चक्कर कम होते हैं और पीक आवर्स के दौरान यात्रियों की आवाजाही बेहतर होती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतीक्षा का समय और कुल यात्रा समय कम हो जाता है। कनेक्टिविटी की वजह से लिफ्ट और एस्केलेटर के रखरखाव का तरीका भी बदल रहा है। ग्रीन बिल्डिंग के ऊंचे मानकों के लिए डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स को आम बातों से आगे सोचने की जरूरत है। 'स्मार्ट वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन' (जैसे लिफ्ट और एस्केलेटर) को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बेहतरीन सुविधाओं वाला एक स्मार्ट सिस्टम ऊर्जा की खपत कम करने, लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने, सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने और बिल्डिंग के लंबे समय तक सुचारु रूप से काम करने में मदद कर सकता है। इससे बिल्डिंग मालिकों के लिए कई फायदे हैं। ऊर्जा खर्च में कमी, बेहतर विश्वसनीयता और लोगों की संतुष्टि। डेवलपर्स के लिए यह 'ग्रीन-बिल्डिंग सर्टिफिकेशन' हासिल करने का एक मजबूत जरिया बन सकता है, क्योंकि यह ऊर्जा-दक्षता क्रेडिट पाने और बिल्डिंग के कुल प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। शहरों के लिए यह शहरी आवागमन के विकास की दिशा में एक और कदम है- जिसमें हर बार एक वर्टिकल सफर (ऊपर-नीचे की यात्रा) अहम भूमिका निभाती है।

ऑपरेशन आर्म्स क्लीन के तहत गैंग का सफाया

संचार जगत

बानसूर। अवैध हथियारों और इनामी अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन आर्म्स क्लीन के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात रू8584 गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लाख 25 हजार रुपये के सात इनामी बदमाशों को दबोचा है और उनके कब्जे से 14 अवैध हथियार और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के कब्जे से 10 देशी कट्टे, 3 देशी पिस्टल, 1 देशी रिवॉल्वर, 2 मैगजीन, 15 जिंदा कारतूस और दो कपड़े के बैग बरामद किए हैं।



चिकित्सा शिक्षा विभाग में 209 सहायक आचार्य नियुक्त

संचार जगत



जयपुर। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में फैकल्टी की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 23 विशिष्टताओं में 209 चयनित सहायक आचार्यों के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि 2021 में सहायक आचार्य भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी। 6 नवम्बर को न्यायालय से रोक हटने के बाद विभाग ने आवश्यक कार्यवाही पूरी कर 18 नवम्बर को 209 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। शेष अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त होने पर उनके नियुक्ति आदेश भी नियमानुसार जारी किए जाएंगे। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा आमजन को बेहतर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

एग्रीगेटर नीति लागू करने में राजस्थान प्रथम



संचार जगत

जयपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार द्वारा केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 को राज्य में लागू करने की पहल की सराहना करते हुए राजस्थान को देश का पहला राज्य बताया है, जिसने इन दिशा-निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू किया है। उन्होंने अन्य राज्यों से भी राजस्थान की तर्ज पर एग्रीगेटर नीति को अपनाने का आह्वान किया। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने राजस्थान को देश का पहला राज्य बताया, जिसने केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 को राज्य में पूर्ण रूप से लागू किया है। कार्यक्रम में देश में एग्रीगेटर एवं डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, आजीविका के अवसरों, चालक कल्याण तथा सुरक्षित और समावेशी परिवहन व्यवस्था के विकास पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2025 को जारी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस के अनुरूप राजस्थान ने नियम बनाकर उन्हें लागू किया है। कार्यक्रम में राजस्थान की पहल को मिली सराहना राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण और रोजगारोन्मुखी परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान है।

राजस्थान में दिखेगा चक्रवात अकवान का हल्का असर

संचार जगत

जयपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय भीषण चक्रवाती तूफान अकवान का अप्रत्यक्ष और हल्का प्रभाव आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यद्यपि इस चक्रवात का सीधा असर राजस्थान पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके प्रभाव से कोटा संभाग के मौसम में बदलाव होने की संभावना है और वहां हल्के बादल छा सकते हैं। दूसरी ओर, प्रदेश में चल रही उत्तरी हवाओं के कारण शेखावाटी क्षेत्र और बीकानेर संभाग में रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सर्दी का असर और तेज होगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज अकवान के आंध्रप्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है, जिसका सीधा असर 8 राज्यों में दिखेगा। राजस्थान में अगले तीन दिन मौसम साफ रहने और तापमान में गिरावट के साथ शेखावाटी और बीकानेर संभाग में रात की सर्दी बढ़ने के आसार हैं, जबकि कोटा संभाग में अगले सप्ताह बादलवाही हो सकती है।

पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण जारी

संचार जगत



भीलवाड़ा। विधिक माप विज्ञान विभाग के नियंत्रक द्वारा गठित विशेष दल की ओर से जिले में पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। अभियान के तहत बुधवार को टीम ने भीलवाड़ा बाईपास स्थित पेट्रोल पंप प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री दाता एचपी सेंटर पर सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं पाए जाने पर नियमानुसार शास्ति वसूल की गई। निरीक्षण के दौरान सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति निर्धारित मात्रा के अनुरूप सही पाई गई। टीम द्वारा दाता एचपी सेंटर, विराट पेट्रोलियम, गर्ग पेट्रोलियम, एचएसडी साइट, डीके फिलिंग स्टेशन एवं यूएचएफ फिलिंग स्टेशन पर निरीक्षण की कार्रवाई की गई।

मोदी ने खेल के जरिए बताया देश की बदलती तस्वीर

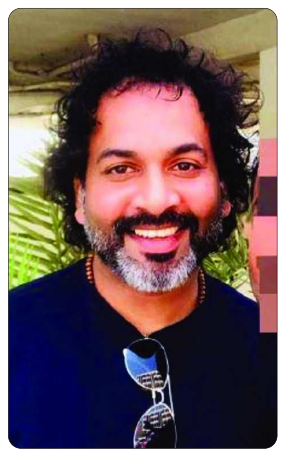
संचार जगत



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय वीडियो गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 से प्रेरित एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने कई क्षेत्रों में भारत के बदलावों को रेखांकित किया और जीटीवी 5 तथा जीटीए 6 के रिलीज होने के बीच के समय में देश की प्रगति की तुलना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने कई स्लाइड्स साझा कीं, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में भारत की उपलब्धियों को दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि भारत अब एक बिल्कुल अलग स्तर पर खेल रहा है। इसमें उन्होंने भारत के आर्थिक बदलाव, अत्यधिक गरीबी में 27 प्रतिशत की कमी, स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति, भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास, देश में बिजली पहुंचाने की प्रगति और देश के डिजिटल बदलाव को दर्शाया। इस पोस्ट में वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की बदलती स्थिति को भी दिखाया गया है।

कानून के शिकंजे में आया खूंखार हत्यारा

संचार जगत



कोच्चि। कानून के लंबे हाथों से बचकर विदेश में छिपे अपराधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक और बड़ी कामयाबी मिली है।

सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और केरल पुलिस के साथ मिलकर सटीक समन्वय बिठाते हुए भगोड़े राघेश उन्नीकोचन को संयुक्त अरब अमीरात से डिपोर्ट कराकर भारत लाने में सफलता हासिल की है। 2008 के एक सनसनीखेज हत्याकांड में वांछित और इंटरपोल के रेड नोटिस का सामना कर रहे इस आरोपी को केरल पुलिस की विशेष टीम यूएई से लेकर तिरुवनंतपुरम पहुंची। राघेश उन्नीकोचन केरल के त्रिशूर जिले के तिरुमंगलम में 1 अक्टूबर, 2008 को हुई एक जघन्य हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। वारदात के बाद कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए राघेश देश छोड़कर फरार हो गया था।

जापान में 5.7 तीव्रता का भूकंप, लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह

संचार जगत



टोक्यो। दक्षिण-पश्चिमी जापान के कुमामोटो प्रान्त में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।

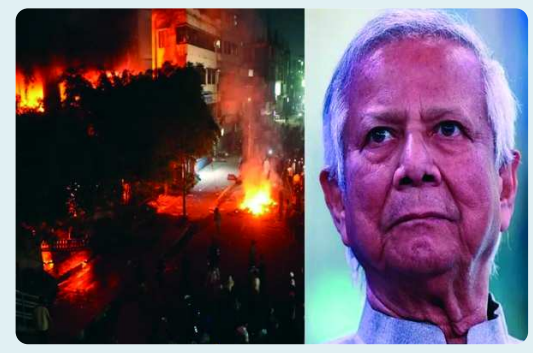
रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.7 मापी गई। जापान की मौसम एजेंसी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि लोगों को लगभग एक हफ्ते तक सतर्क रहना होगा, क्योंकि इसी तीव्रता का एक और भूकंप आ सकता है। भूकंप स्थानीय समयानुसार तड़के 2:22 बजे आया। इसका केंद्र अमाकुसा-अशिकीता क्षेत्र में था और यह जमीन से लगभग 10 किमी की गहराई पर आया था।

स्थानीय प्रशासन ने मिनामाता और कुमा के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया। साथ ही, हाकाता और कागोशिमा-चूओ स्टेशनों के बीच क्यूशू शिंकानसेन बुलेट ट्रेन की आठ सेवाएं रोक दी गईं, जिससे लगभग 5,600 यात्री असमंजस की स्थिति में रहे। भूकंप के झटके जापान के दक्षिण-पश्चिमी मुख्य द्वीप 'क्यूशू' के साथ-साथ शिकोकू और होन्शू के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए।

इससे पहले 28 जुलाई को कुमामोटो प्रान्त में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। उस समय जापान के भूकंप पैमाने पर कुछ इलाकों में अधिकतम तीव्रता 7 दर्ज की गई थी।

1 अगस्त के बाद से, गुरुवार को आया यह पहला भूकंप है जिसकी तीव्रता 5 या उससे अधिक दर्ज की गई है।

बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा



संचार जगत

ढाका। बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं के बीच चटगांव में पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर में बुधवार रात आग लगा दी गई। पुलिस ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। वहीं, गोपालगंज में भी हिंसक वारदातें रिपोर्ट की गईं। बताया जा रहा है कि चटगांव के पंचलैश इलाके में स्थित यूनुस के पैतृक आवास के भूतल पर बने एक खाली कमरे में रात करीब 11:30 बजे आग लगाई गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इमारत के भूतल पर कोई नहीं रहता है। घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर प्रोफेसर यूनुस के दो भाइयों के परिवार रहते हैं।

मोइली ने मोदी के खिलाफ दिया विवादित बयान



कहा-कांग्रेस ने मोदी को जेल जाने से बचाया था

संचार जगत

बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने विवादित बयान में कहा है कि जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी, उस समय उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाया था। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने एक कार्यक्रम में कहा कि जब मैं कानून मंत्री था, तब हमारे नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाया था। कांग्रेस को उसी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती थी। मोइली ने कहा कि अदालत ने अमित शाह को उनके गृह राज्य गुजरात से निष्कासित कर दिया था और मामला भी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। जेल जाने वाले पहले व्यक्ति अमित शाह थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी की बारी आई। उन्हें भी जेल जाना पड़ता और राज्य से निष्कासित होना पड़ता। यह सब हमारी पार्टी की त्रासदी है। हमारी ही पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रोक दी गई। यह यूपीए सरकार के दौरान हुआ और यह पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की वजह से नहीं बल्कि अन्य नेताओं की वजह से हुआ था। नतीजा यह है कि आज हम भुगत रहे हैं। मोइली ने यह भी कहा कि अगर पार्टी के भीतर यथास्थिति बनाए रखने की चाह रखने वाले कुछ नेताओं ने रुकावट न डाली होती, तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती थी।

मध्य पूर्व में अमेरिकी विमानवाहक पोतों की संख्या तीन से घटकर दो रह गई

अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी नौसैनिक तैनाती में बदलाव किया गया

संचार जगत



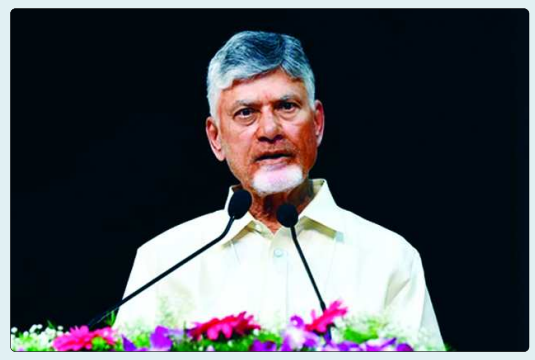
वाशिंगटन। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी नौसैनिक तैनाती में बदलाव किया है। परमाणु ऊर्जा से संचालित अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन इस क्षेत्र से लौट गया है।

इसके साथ ही मध्य पूर्व में अमेरिकी विमानवाहक पोतों की संख्या तीन से घटकर दो रह गई है। अमेरिकी प्रशांत बेड़े के प्रवक्ता ने बताया कि जापान में तैनात यह विमानवाहक पोत मध्य पूर्व में तीन महीने की तैनाती पूरी करने के बाद अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े में लौट आया है।

फिलहाल यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सामान्य सैन्य गतिविधियों में शामिल है। ईरान के साथ अमेरिकी संघर्ष के दौरान अमेरिकी विमानवाहक पोतों ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले सोमवार को अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट मध्य पूर्व पहुंचा था। इससे पहले इस क्षेत्र में यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश और यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन तैनात थे।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब वाशिंगटन और तेहरान के बीच कूटनीतिक प्रयास ठप पड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले फिर शुरू करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।

नायडू ने बिजली की बढ़ती मांग से निपटने के दिए निर्देश



संचार जगत

अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। पिछले साल की तुलना में, इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच बिजली की मांग में 18.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय में ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा चर्चा की। इनमें ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, नई परियोजनाओं की प्रगति, बिजली की खपत पर अल नीनो का असर और इसके कारण बिजली की मांग में हुई बढ़ोतरी शामिल है। इसके अलावा, मांग-आपूर्ति की स्थिति, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3, पंपड स्टोरेज परियोजनाओं और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जैसे विषयों पर भी बातचीत हुई। चर्चा का मुख्य केंद्र विशाखापत्तनम में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ पार्टनरशिप समिट के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में मिले निवेश और इन परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के उपायों पर भी रहा।

बंगाल कैश बरामदगी मामला: फरार चल रहे विधायक के घर पहुंची सीआईडी

संचार जगत



कोलकाता। पश्चिम बंगाल की आपराधिक जांच विभाग टीम ने एआईटीएमसी कार्यालय से करीब एक करोड़ रुपए बरामद होने के मामले में फरार चल रहे पार्टी विधायक शमीम अहमद की तलाश तेज कर दी है। सीआईडी टीम ने बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात एआईटीएमसी विधायक के आवास पर छापा मारा, लेकिन बैरंग लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार, फरार विधायक काफी समय से हिंगचेबेरिया स्थित अपने आवास पर नहीं रह रहे हैं। यह कार्रवाई जिले के सरिशा में पार्टी कार्यालय से हाल ही में लगभग 1.03 करोड़ रुपए नकद बरामद होने के मामले की जांच के सिलसिले में की गई। इसके अलावा, शमीम अहमद के खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। अहमद उन चुनिंदा विधायकों में से हैं, जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के प्रति वफादार माने जाते हैं।

उन पर लगे मुख्य आरोपों में बंदूक की नोक पर दूसरों की जमीन हड़पना और अपने इलाके में बड़े पैमाने पर जबरन वसूली करना शामिल है। फिलहाल, एआईटीएमसी विधायक फरार चल रहे हैं और पुलिस टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं।

सुवाना स्थित रूट सेट संस्थान में ब्लॉक स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक आयोजित

संचार जगत



भीलवाड़ा। सुवाना स्थित रूट सेट संस्थान में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विजयपाल वर्मा की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पीईईओ, यूसीईईओ एवं प्रधानाचार्यों को संस्थान की ओर से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। संस्थान में 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के महिला एवं पुरुषों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क रहती है। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर संस्थान की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो पूरे भारत में मान्य है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने में कर सकते हैं। बैठक में ब्लॉक रैंकिंग के विभिन्न मानकों, शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति, अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व आवश्यक तैयारियां करने, विध्या संबलन योजना के क्रियान्वयन और ड्रॉप आउट एवं अनामांकित छात्र-छात्राओं को पुनः विद्यालयों से जोड़ने सहित कई विषयों पर चर्चा की गई।

भाखड़ा नहर पर बना बेली स्टील पुल ढहा

संचार जगत



चंडीगढ़। पंजाब में पटियाला-संगरूर-बठिंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यहां पासियाना गांव के पास भाखड़ा नहर पर बना स्टील का बेली-टाइप पुल उस समय ढह गया, जब उस पर से दो ट्रक गुजर रहे थे। अचानक पुल ढहने से दो भारी वाहन उसके क्षतिग्रस्त हिस्से में फंस गए। इनमें से एक ट्रक में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं। किसी की जान जाने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि पुल ढहने के बाद भाखड़ा नहर का पानी पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बहने लगा। इस पुल का निर्माण 2016 में हुआ था। यह मार्ग पटियाला, संगरूर और बठिंडा के बीच एक अहम कड़ी है, जहां से बड़ी संख्या में कमर्शियल और यात्री वाहन गुजरते हैं।

बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्पंदन अभियान शुरू किया

बंदियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल

संचार जगत



भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से जेलों में निरुद्ध बंदियों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। अभियान की मूल भावना स्वास्थ्य, आशा और मानवता पर आधारित है।

जेलों में निरुद्ध कई बंदियों को गंभीर बीमारियों, विशेष जांच अथवा विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार की आवश्यकता होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए रालसा ने स्पंदन अभियान की पहल की है। अभियान के तहत बंदियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

इसके अंतर्गत राजकीय चिकित्सालयों की मेडिकल टीमें समय-समय पर जेलों में पहुंचकर बंदियों की स्वास्थ्य जांच करेंगी। इन टीमों के साथ अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे एवं नेत्र परीक्षण जैसी आवश्यक जांचों के लिए पोर्टेबल उपकरणों की सुविधा भी उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इससे सामान्य एवं आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सा जांच के लिए बंदियों को बार-बार जेल से बाहर ले जाने की जरूरत कम होगी। इसी क्रम में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्पंदन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बंदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक चर्चा की गई।

तेजस्वी ने सरकार पर लगाया संविधान की अवहेलना का आरोप

संचार जगत



पटना। बिहार में एक मंत्री की शैक्षणिक नियुक्ति और लियन लेने की प्रक्रिया को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में राज्य सरकार पर संविधान और नियमों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने संबंधित मंत्री की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने और उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाने की मांग की है। हालांकि, अपने बयान में तेजस्वी यादव ने संबंधित मंत्री का नाम नहीं लिया। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि बिहार सरकार ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ महीनों से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए रखा गया है, जिसकी एक साथ तीन पदों पर बने रहने की वैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोक भवन ने भी एक ही व्यक्ति के एक साथ मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद के पद पर रहने पर गहरी आपत्ति जताई है।

पंजाब में जनता बदलाव के लिए तैयार : पायलट

संचार जगत



मोहाली। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने राज्य की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता बदलाव के लिए तैयार है और लोग बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। पायलट ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रही है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार काफी अच्छा चल रहा है। राहुल गांधी की ओर से शुरू किए गए साइकिल मार्च और इंसाफ रैली के बाद लगातार लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता अब बदलाव चाहती है और आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पायलट ने कहा कि राज्य से रोजाना जबरन वसूली, फिरौती की मांग, गैंगस्टरों और नशीले पदार्थों से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं।

नदी में गिरी स्कॉर्पियो, छह लोगों की मौत



संचार जगत

अररिया। बिहार के अररिया जिले में एक सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। तिलक समारोह से लौट रहे लड़की पक्ष के लोगों से भरी एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पुल से नीचे मरिया नदी में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो में सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के बीड़ी पुल पर हुआ। स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के थुमहा गांव के निवासी थे। वे अररिया जिले के सिकटी प्रखंड स्थित भपटिया गांव में आयोजित तिलक समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बीड़ी पुल के तीखे मोड़ पर चालक स्कॉर्पियो पर से नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित वाहन सीधे पुल की रेलिंग पार करते हुए नीचे मरिया नदी में जा गिरा। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि अन्य छह लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी।

देश भर में इंदिरा गांधी जी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि दी



संचार जगत

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इंदिरा गांधी को अदम्य साहस, संघर्ष और सशक्त नेतृत्व की प्रतीक बताया। उन्होंने लिखा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, योगदान, दृढ़ इच्छाशक्ति और निर्णायक नेतृत्व सदैव हमारी प्रेरणा बना रहेगा। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन किया। एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार ने पोस्ट में लिखा कि मुश्किल दौर में देश का नेतृत्व करते हुए इंदिरा गांधी ने भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई।

भारत ने पाकिस्तान को दी करतूतों से बाज आने की हिदायत



संचार जगत

नई दिल्ली। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को अपनी करतूतों से बाज आने की हिदायत दी है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवतानेनी हरीश ने सुरक्षा परिषद में इस्लामाबाद को आईना दिखाते हुए माना कि उनकी सेना का हस्तक्षेप देश को बर्बाद कर रहा है। पी. हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में आरिया-फॉर्मूला बैठक के दौरान भारत का स्पष्ट मत रखा। संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक का विषय प्राकृतिक संसाधनों और शांति के बीच संबंध तथा इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नियमों की संभावित कमियों का आकलन था। इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन किस तरह संघर्षों को बढ़ावा देने या शांति और विकास का आधार बनने में भूमिका निभा सकते हैं।

कार्मिक विभाग सचिव ने किया संपर्क हेल्पलाइन का निरीक्षण

संचार जगत



जयपुर। कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण कर यहां संचालित व्यवस्थाओं एवं परिवादों के निस्तारण की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाले परिवादों की प्रकृति, वर्गीकरण एवं निस्तारण की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। सिंह ने कहा कि हेल्पलाइन के माध्यम से विभाग को प्राप्त होने वाले सभी प्रकरण अनिवार्य रूप से शिकायत की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि इनमें नीतिगत विषयों, व्यक्तिगत मामलों एवं विभिन्न मांगों से संबंधित प्रकरण भी शामिल होते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का उनकी प्रकृति के अनुरूप पृथक-पृथक वर्गीकरण किया जाए तथा विषयों का समुचित मॉडरेशन सुनिश्चित किया जाए। इससे प्रकरणों का सही विश्लेषण संभव हो सकेगा और प्रत्येक प्रकरण के अनुरूप समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। निरीक्षण के दौरान सिंह ने वीडियो कॉल के माध्यम से जयपुर निवासी परिवादी संजीव से भी संवाद किया।

हरदीप सिंह पुरी ने ईंधन के दाम घटने का किया दावा

संचार जगत



नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते चार वर्षों में देश में ईंधन के दामों में कटौती हुई है। नई दिल्ली में फिक्की की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कमी किए जाने के कारण बीते चार वर्षों में देश में ईंधन की कीमतों में कमी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2026 में एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। इसका उद्देश्य ईंधन को सभी लोगों की पहुंच में बनाए रखना था। पुरी ने कहा कि वैश्विक ईंधन आपूर्ति से जुड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। होर्मुज स्ट्रेट को खोलने को लेकर अमेरिका, ईरान और खाड़ी के देशों के बीच बातचीत चल रही है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को राहत करार

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की श्रेष्ठ की याचिका



संचार जगत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को मिली अंतरिम जमानत भी बरकरार रखी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने सुनवाई करते हुए आजम खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। अंतरिम जमानत देते वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी को लेकर शुरुआती राय का मामले के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही वे रामपुर जिला जेल से एक अलग मामले में जमानत पर बाहर आए थे। हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद आजम खान को बुधवार को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा किया गया।

सियोल में आयोजित आईआईएएस 2026 सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक संस्थान के अध्यक्ष के रूप में सियोल घोषणा पत्र पर मुख्य सचिव ने किए हस्ताक्षर



संचार जगत

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में सियोल घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। सियोल में आयोजित आईआईएएस 2026 सम्मेलन के दौरान उन्होंने लोक प्रशासन संस्थाओं और भागीदार संगठनों के प्रमुखों के साथ आर्थिक विकास को लोगों के जीवन में स्थायी सुधार से जोड़ने की साझा प्रतिबद्धता जताई। घोषणापत्र की पांच प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए वी. श्रीनिवास ने कहा कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए सरकार की सक्रिय भूमिका के साथ उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग जरूरी है। उन्होंने नीति निर्माण में नागरिकों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्मिकों की सार्थक भागीदारी पर भी जोर दिया। सामाजिक नवाचार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक समस्याओं के सफल समाधानों की पहचान कर उन्हें व्यापक स्तर पर अपनाने की जरूरत है। कानूनी, संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार से इस प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। टेक्नोलॉजी और डेटा का जिम्मेदारी से उपयोग भी इन प्रयासों को मजबूत बनाने में सहायक होगा।

रक्षा तकनीक में साथ आएंगे भारत और जापान

संचार जगत



नई दिल्ली। भारत-जापान रक्षा सहयोग को नई रफ्तार देने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा से लेकर मिसाइल तकनीक तक मिलकर काम करेंगे।

टोक्यो में चौथी भारत-जापान वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अहम बातें साझा की हैं। दोनों देश समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में आयोजित वार्ता के बाद बताया कि भारत और जापान एशिया के दो मजबूत लोकतांत्रिक देश हैं और विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। यह साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान जैसे भरोसेमंद साझेदारों का महत्व और बढ़ गया है। जयशंकर ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक परिदृश्य भी जटिल बना हुआ है। भारत और जापान इस क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रयास में दोनों देशों के साथ अन्य क्वाड साझेदार भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की बदलती परिस्थितियों में पुरानी मान्यताओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अब प्रत्येक देश को वैश्विक हित में पहले से अधिक योगदान देना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर, द्विपक्षीय साझेदारी के माध्यम से और समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर पहल करनी होगी।

गुंडों को ढूंढकर ऐसी सजा देंगे, कई पीढ़ियां याद रखेंगी- मुख्यमंत्री योगी

संचार जगत



गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान एक किशोर की मौत पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे निर्मम हत्या करार दिया है। उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिया कि सड़क पर अराजकता फैलाने वाले गुंडों को ढूंढ़ निकालें और उन्हें ऐसी कठोर सजा दिलाएं, जिसे उनकी कई पीढ़ियां याद रखें।

गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुधवार को समाजवादी पार्टी का एक रोड शो था। उन्होंने एक नाबालिग लड़के को अपने रोड शो का शिकार बना दिया। सपा गुंडागर्दी, दंगे, अराजकता और कर्फ्यू की प्रायः है। यह माफिया सपा का सगा है और जनता के साथ इस पार्टी ने हमेशा धोखा दिया है।

उन्होंने कहा कि जिन गुंडों ने सड़कों पर अराजकता फैलाई, हमने अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। हमने प्रशासन से कहा है कि गुंडों को ढूंढ निकालो और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कई पीढ़ियां याद रख सकें। सीएम योगी ने कहा, 'प्रदेश की सड़कें आम जनमानस के सुगम आवागमन के लिए बनी हैं, न कि सपा और कांग्रेस के गुंडों की अराजकता के लिए। अगर किसी ने दोबारा माफियागिरी दिखाने का दुस्साहस किया, तो उस माफिया को भी मिट्टी में मिलाने में देर नहीं लगेगी।

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने चाय पर नागरिकों से किया संवाद



संचार जगत

जयपुर। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 में झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नागरिकों के साथ मॉर्निंग वॉक की, ओपन जिम का शुभारंभ किया और चाय पर लोगों से संवाद किया। सुबह की सैर के दौरान कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और स्थानीय आवश्यकताओं एवं सुझावों पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने ओपन जिम का शुभारंभ करते हुए नियमित व्यायाम, स्वस्थ जीवनशैली और सामुदायिक फिटनेस के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि घर के नजदीक उपलब्ध ऐसी सुविधाएं युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को अपनी दिनचर्या में फिटनेस अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मॉर्निंग वॉक के बाद स्थानीय नागरिकों के साथ चाय पर चर्चा के दौरान क्षेत्र के विकास, जनसुविधाओं और दैनिक जीवन से जुड़े विषयों पर संवाद हुआ। राठौड़ ने कहा कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच संवाद केवल कार्यालयों और औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सुबह की सैर हो या चाय पर चर्चा, लोगों के बीच रहकर उनकी बात सुनना और उनकी आवश्यकताओं को समझना भी जनसेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ग्रीस, स्पेन और नेपाल के राजनयिकों ने राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र सौंपे

राष्ट्रपति ने तीन देशों के राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त किए

संचार जगत



नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान तीन देशों के राजदूतों से उनके परिचय पत्र स्वीकार किए।

ग्रीस, स्पेन और नेपाल के राजनयिकों ने राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में ग्रीस के राजदूत जॉर्जियोस पेटमेजाकिस, स्पेन के राजदूत अल्फ्रेडो मार्टिनेज सेरानो और नेपाल के राजदूत डॉ. निश्चल नाथ पांडे से उनके परिचय-पत्र स्वीकार किए। भारत और ग्रीस के बीच आधुनिक राजनयिक संबंध मई 1950 में स्थापित हुए थे और अगस्त 2023 में इन्हें रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया। ग्रीस ने 1950 में नई दिल्ली में और भारत ने मार्च 1978 में एथेंस में अपना दूतावास खोला। वर्ष 2026 में दोनों इन संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के साथ भारत-स्पेन संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष मना रहे हैं। नेपाल और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की औपचारिक शुरुआत आजादी के ठीक बाद, यानी 17 जून 1947 को हुई थी, और 1950 की शांति एवं मैत्री संधि इन संबंधों का मुख्य आधार है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में नेपाल एक प्राथमिकता वाला साझेदार है। परिचय पत्र समारोह इस महीने में दूसरी बार संपन्न हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 6 नवंबर को भी राष्ट्रपति भवन में माली, म्यांमार, मेडागास्कर और इक्वेटोरियल गिनी के राजदूतों से परिचय-पत्र स्वीकार किए थे।



ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

संचार जगत

कोटपूतली-बहरोड़। बहरोड़ सदर थाना पुलिस ने त्वरित और तकनीकी अनुसंधान के जरिए एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया है। मृतक की पत्नी ने ही अपने पति को रास्ते से हटाने तथा हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देकर बीमा क्लेम उठाने की नीयत से अपने प्रेमी और उसके साथी के जरिए इस वारदात को अंजाम दिलवाया था। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, 11 नवंबर को पीसीआर कोटपूतली से सूचना मिली थी कि वीरमती होटल के पास एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है।

स्वामित्व, प्रकाशक एवं संपादक : अवंतिका राठौड़ - पी.के. प्रिंटर्स एंड स्टेशनर्स, 31, राम मंदिर के पास, पटेल नगर, 22 गोदाम, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। कार्यालय : जे-17, रमेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर। संपर्क : 0141 463 7668
ई-मेल : sancharjagat@gmail.com| आरएनआई नं. : RAJHIN/2014/55262 समाचार चयन के लिए पीआरबी अधिनियम के तहत जिम्मेदार। न्यायाधिकार क्षेत्र : जयपुर महानगर।